में पहले चरण में 14 सड़कों के निर्माण तथा दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के अनुमान शामिल किए गए थे। इनमें से, राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के अनुसार 14 सड़कों, जिनमें दूसरे चरण की एक सड़क भी शामिल है, को 1985-86 तथा 1986-87 में अनुमोदित कर दिया गया था। सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार से 10 अन्य सड़कों के निर्माण के लिये भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पहले से स्वीकृत कार्यों की असंतोषजनक प्रगति तथा राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से 10 सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका। इस योजना को 1992-93 में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

Socio Economic Development in Arunachal Pradesh

84042-G SHRI NYODEK YONG-GAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rural Works Department (RWD) of Arunachal Pradesh have helped achieving Socio-economic development of the people of Arunachal Pradesh; and

(b) if so, the details thereof with effect from 1989 onwards.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) During the last two years i.e. 1989-90 and 1990-91, various developmental activities were taken up by the Rural Works Department (RWD) for uplift-ment of Socio Economic conditions of the poor people of Arunachal Pradesh. Some of the achievement made during this period were; (i) more than 5500 hectares of land added for assured irrigation (ii) 260 villages fully covered and 44 villages partially covered under Rural Water Supply Programme, (iii) 95 Filtration Plants for water supply purposes installed, (iv) 141 Kms. fair weather roads constructed alongwith 24 suspension bridges, 49 culverts under rural link road programme. In the soil sector, more than 4500 heetars of land protected and about 700 hectares of land developed for cultivation. 20 Bio-Gas Plants installed. About 2700 improved chulhas distri buted and installation of 106 solar P. V. street lights done.

Previously Unstarred Question 4320, transfeirrad from the 27th March, 1992.

जल-परीक्षण प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाना

\$\$4042—ज. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में प्रत्येक जिले में एक जल-परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विगत में चलती फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की अनुमति दी थी और क्या ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1989—90 से 1991—92 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 110 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया है। आठवीं योजना में नीति और परिव्ययों, जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, के आधार पर सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक जल-जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का है।

\$\$Previously Unstarred Question 4331, transfered from the 27th March, 1992 1992.

(ग) 26 चलती फिरती जल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन किया गया था जिनमें से अभी तक 17 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(घ) अनुमोदित और स्थापित की गई चलती फिरती प्रयोगशालाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	राज्य	चलती फिरती प्रयोगशालाओं की संख्या	
		अनुमोदित	सप्लाई की गई
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
2.	असम	1	—
3.	गुजरात	1	1
4.	हरियाणा	1	—
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1
6.	जम्मू व कश्मीर	3	—
7.	मध्य प्रदेश	1	1
8.	महाराष्ट्र	1	1
9.	मणिपुर	1	1
10.	मेघालय	1	1
11.	मिजोरम	1	1
12.	नागालैंड	1	1
13.	उड़ीसा	1	1
14.	राजस्थान	1	1
15.	सिक्किम	1	1
16.	तमिलनाडु	1	1
17.	त्रिपुरा	1	—
18.	उत्तर प्रदेश	1	1
19.	पश्चिमी बंगाल	1	—
20.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	—
21.	दिल्ली	1	1
22.	अन्य संस्थाएं	3	2
	कुल	26	17

(ङ) मध्य प्रदेश के बस्तर, बैतुल झबुआ, रायगढ़, रायबढ़ और शाडौल जिलों में 6 प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। राज्य सरकार ने राजापुर, शिवपुरी, मुरैना, सिधी, सागर, जबलपुर, बिलासपुर, सिओनी खडवा और मडसौर जिलों में 10 और जिला जल जांच प्रयोगशालाए स्थापित करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से कुछेक मुददों पर स्पष्टीकरण मागें गए थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

12.00 NOON

[The Deputy Chairman in the Chair.]

STATEMENT BY MINISTER

Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 12th March 1992 to starred question 233 regarding feed-stock for new fertilizers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICAL* AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : Madam..... *(.Interrup tions)*

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): What is the reply ? What is he saying?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Chinta Mohan, if you come a little forward, they may hear it. If you come in front, they can hear what you are saying.

आप आगे आ जाइए। आपको प्रमोट कर देते हैं। बोलिए आपने क्या कहा। दोबारा बोल दीजिए।

श्री दीपेन घोष: आपका जवाब तो नहीं सुन पाए, इसका क्लैरिफिकेशन सुन लेते हैं।

SHRI CHINTA MOHAN : Madam, I invite the attention of the House to the reply given to Starred Question No. 233 in this House on 12th March, 1992. In reply to part (d), the following addition may kindly be made after S. No. (iii)

"(iv) The three fertilizer plants at Vijaipur, Aonla and lagadishpur which are operational and three fertiliser projects at Gadepan, Babrala and Shahjahanpur which are under implementation."

The above omission was due to inad-vertence.

[Placed in Liberary *See* No. LT-1723/ 92].

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1990-91) of the Nehru .Institute of Mountaineering Urtarkashl and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCB (SHRI S.KRISHNA KUMAR): Madam